



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 488]
No. 488]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 1983/पौष 5, 1905
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 1983/PAUSA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेशी-कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1983

अधिसूचना

आय-कर

सा० का० नि० 920 (अ) :- भारत गणराज्य की सरकार और मौरिशस सरकार के बीच, दोहरे कराधान के परिष्करण करने के लिए तथा आय और पूंजी अभिलाभ पर करों की बाबत राजवित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए तथा पारस्परिक व्यापार और वित्तियान को प्रोत्साहन देने के लिए इनके उपाखण्ड कन्वेंशन, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अपनी अपनी विधियों की अपेक्षानुसार प्रक्रियाएँ पूरी कर देने के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित कर देने पर जो उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 द्वारा अपेक्षित है, प्रवृत्त हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90-क और कंपनी (लाभ) अनिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24-क द्वारा प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के तर्मा उपबन्धों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार तथा मौरिशस की सरकार के बीच दोहरे कराधान के परिहार और आय तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार तथा मौरिशस की सरकार दोहरे कराधान के परिहार के लिए और आय तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा पारस्परिक व्यापार एवं निवेश के प्रोत्साहन के लिए अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है .

अध्याय 1

अभिसमय का क्षेत्र

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों सविदाकारी राज्यों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय जिन मौजूबा करों पर लागू होगा वे हैं .

(क) भारत में :

(i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन लगाया गया आयकर जिसमें आयकर पर कोई अतिमात्र भी शामिल है,

(ii) कम्पनी (सार्व) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन लगाया गया अधिनियम, (इसके बाद 'भारतीय कर' कहा गया है) ;

(ख) मारीशस में :

आयकर (इसके बाद 'मारीशस कर' कहा गया है)।

2. यह अधिसूचना, निम्नी गमरूप अथवा मारतः वैने ही करें पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में उल्लिखित मोझदा करों के अनिरुक्त अथवा उनके स्थान पर, वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद लगाए गए हों।

3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अध्याय 11

परिभाषाएं

अनुच्छेद 38

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो : (क) 'भारत' शब्द से अभिप्रेत है भारत का क्षेत्र और उसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके उपर आकाश क्षेत्र तथा प्रादेशिक समुद्र, महाद्वीपीय जल सीमा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र 'अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 80) में उल्लिखित कोई भी अन्य ऐसा समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारत के कृषिपय अधिकार हों और उस सीमा तक उनमें इन अधिकारों का उसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है मानों वह, समुद्रीय क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र का एक भाग हो ;

(ख) 'मारीशस' शब्द से अभिप्रेत है वे सभी क्षेत्र जिसमें सभी द्वीपीय समूह भी शामिल है जिसमें, मारीशस के कानूनों के अनुसार, मारीशस बनता है और निम्नलिखित को शामिल करता है :-

(i) मारीशस का सामुद्रिक क्षेत्र, और

(ii) मारीशस के प्रादेशिक समुद्र से बाहर वह क्षेत्र भी शामिल है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, महाद्वीपीय जल सीमा के संबंध में मारीशस कानूनों के अधीन ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है या इसके बाद किया जाएगा जिसमें समुद्रतल और अवभूमि और उनके प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में मारीशस के अधिकारों का प्रयोग किया जा सकेगा।

(ग) 'संविदाकारी राज्य' और 'अन्य संविदाकारी राज्य' शब्द से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारत या मारीशस अभिप्रेत हैं।

(घ) 'कर' शब्द से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारतायकर अथवा मारीशस कर अभिप्रेत है किन्तु इसमें ऐंभी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में ऐंसी किसी भूक अथवा भूल के सम्बन्ध में देय हो जिन पर यह अधिसूचना लागू होता है जयवा जो ऐसे अर्थदण्ड को रकम हो जो उन करों के सम्बन्ध में लगाया गया हो ;

(ङ) 'व्यक्ति' शब्द में कोई व्यक्ति कम्पनी और कोई अन्य सत्ता, निगमित अथवा गैर-निगमित शामिल हैं जिन्हें अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अधीन कर योग्य एकक के रूप में समझा जाता है ;

(च) 'कंपनी' शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ऐंसी इकाई अभिप्रेत जो अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अधीन कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है

(छ) 'एक संविदाकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम' शब्दों से संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम क्रमशः औद्योगिक, खनन, वाणिज्यिक, वागान या कृषि उद्यम या इसी प्रकार के कारखाने तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम क्रमशः औद्योगिक, खनन, वाणिज्यिक वागान या कृषि उद्यम या इसी प्रकार के कारखाने अभिप्रेत है ;

(ज) 'सक्षम प्राधिकारी' शब्द से अभिप्रेत है, भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, और मारीशस के मामले में आयकर आयुक्त अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(झ) 'राष्ट्रिय शब्द' से अभिप्रेत है संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति और कोई विधिक व्यक्ति, भागीदार अथवा संस्था जो संविदाकारी राज्य के प्रवृत्त कानूनों से अपनी हैसियत प्राप्त करते हैं ;

(ञ) 'अन्तर्राष्ट्रीय यातायात' पद से अभिप्रेत है, किसी उद्यम द्वारा संचालित जहाज या वायुयान द्वारा किया जाने वाला परिवहन मियाय ऐंसी स्थिति में जब एक उद्यम द्वारा जहाज अथवा वायुयान अन्य संविदाकारी राज्य में मात्र दो स्थानों के बीच संचालित किए जाने हों जिसका वास्तविक प्रबंध संविदाकारी राज्य में स्थित हो।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों के प्रवर्तन में किसी भी पद का जो यहाँ परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के उन करों से सम्बन्धित कानूनों के अंतर्गत होता है जो इस अधिसूचना के विषय हैं।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन से, 'संविदाकारी राज्य का निवासी' शब्द से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार अपने अधिवास, निवास, प्रबंध का स्थान या इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण उसमें कर लगने योग्य है। 'भारत का निवासी' और 'मारीशस का निवासी' शब्दों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उसकी निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी :-

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसका स्थायी निवास गृह हो। यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास गृह हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (जिसे इसके बाद 'महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र' के रूप में उल्लेख किया जाएगा) ;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास गृह नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका व्यावहारिक आवास हो ;

(ग) यदि उसका व्यावहारिक आवास दोनों संविदाकारी राज्यों में है अथवा इनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्य के समक्ष प्राधि-

कारी राज्य के सश्रम प्राधिकारी पारस्परिक सझूमति द्वारा हम प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. अज्ञा व्यक्ति में बिना कोई व्यक्ति, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के अनुसार दोनों संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध है।

अनुच्छेद 5

स्थायी स्थापन

(1) इस अभिनमय के प्रयोजन के लिए 'स्थायी स्थापन' पद का अर्थ होगा कारोबार का वह निश्चित स्थान जिसके माध्यम से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

(2) "स्थायी स्थापन" पद में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान ;
- (ख) शाखा ;
- (ग) कार्यालय ;
- (घ) कारखाना ;
- (ङ) कार्यशाला ;
- (च) जो व्यक्ति दूसरों को भंडारण की सुविधाएं देता हो, उसका किया माल गोदाम ;
- (छ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआं, खदान अथवा ऐसा कोई अन्य स्थान जहां से प्राकृतिक संपदाएं निकाली जाती हैं ;
- (ज) फार्म, बाग अथवा ऐसा स्थान जहां कृषि, वन संपत्ति, बाग अथवा उनसे संबंधित कार्य-कलाप किये जाते हैं ;
- (झ) कोई भवन स्थल अथवा निर्माण, सामूहिक परियोजना अथवा उससे संबद्ध पर्यवेक्षी कार्यवाही, जहां इस प्रकार का स्थान, परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यवाही नौ महीने से अधिक अवधि तक जारी रहती है।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होने हुए भी "स्थायी स्थापन" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :—

- (क) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भंडारण अथवा उसके प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) केवल भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टोक रखना ;
- (ग) अन्त उद्यम द्वारा सार्वजनिक के अन्त प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टोक रखना ;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों का गत अथवा सूचना संग्रह के अन्त प्रयोजनार्थ व्यवसाय का निश्चित स्थान रखना ;
- (ङ) केवल व्यापार के लिए निश्चित स्थापन रखना :—
 - (i) विज्ञापन के प्रयोजनार्थ
 - (ii) सूचना देने के लिए ;
 - (iii) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अथवा
 - (iv) इसी प्रकार के निश्चित स्थापन के लिए

जो उद्यम कयापार में का कारोबार अथवा प्रयोग किया की है।

(4) इस अनुच्छेद के पैरा (1) और (2) के उपबन्धों के होने हुए भी, दूसरे संबिदाकारी राज्य के उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर

में किसी संबिदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई ऐसा व्यक्ति (जो स्वतंत्र हैमियत से एजेंट से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 5 लागू हो) प्रथमोलिखित राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन माना जाएगा यदि :—

- (i) उस प्रथमोलिखित राज्य में उस उद्यम के नाम से संबिदाएं सम्पन्न करने का उसे अधिकार है और प्रायः उसका वह प्रयोग करता है, जब तक उसकी गतिविधियां उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य खरीदने तक ही सीमित नहीं हैं; अथवा
- (ii) वह प्रथमोलिखित संबिदाकारी राज्य में प्रायः उस उद्यम के माल अथवा पण्यों का भण्डार रखता हो। जिस में से वह उद्यम की ओर में नियमित रूप से ऑर्डर पूरा करता है।

(5) एक संबिदाकारी राज्य का उद्यम अथ संबिदाकारी राज्य में केवल इस लिए कोई स्थायी स्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी इन्चार्ज, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैमियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है बल्कि कि वहां ऐसा व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप से कर रहे हो। लेकिन जब इस प्रकार के एजेंट के कियेकलाप उस उद्यम की ओर में पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः किए जाते हैं तो इसे इस पैराग्राफ के अन्विष्ट में स्वतंत्र हैमियत का एजेंट नहीं माना जाएगा।

(6) इस तथ्य में कि कोई कम्पनी या किसी संबिदाकारी राज्य की निवासी है, और ऐसा कम्पनी को नियंत्रित करती हो अथवा उसने नियंत्रित होती हो या जो दूसरे संबिदाकारी राज्य को निवासी हो अथवा उस दूसरे राज्य में, (चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम में अथवा अन्यथा) कारोबार करती है उन दोनों में से कोई भी तथ्य स्वतः किसी दूसरी कम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं बन जाएगा।

अध्याय-III

आय का कराधान

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. अचल सम्पत्ति से आय पर कर उस संबिदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिसमें इस प्रकार की सम्पत्ति स्थित है।

2. "अचल सम्पत्ति" शब्दों की परिभाषा उन संबिदाकारी राज्य की विधि तथा रज्जर के अनुसार की जाएगी जिसमें सम्पत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में अचल सम्पत्ति के उपलक्षण के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन सम्पत्ति में पशु पशुधन तथा उरकर शामिल होंगे, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति सम्पत्ति सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हैं, अचल सम्पत्ति का शब्द का अधिकार और खनिज-भण्डार, तेल के कुएँ, खदानों तथा प्राकृतिक संपत्तियों के निवासों के अन्य स्थान, पात, नौकाएं, वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैरा (1) के उपबन्ध अचल सम्पत्ति के पक्ष प्रयोग से कराए पर देने में अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रयोग होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (3) के उपबन्ध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से आय और स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्ठा-वन में प्रयुक्त अचल सम्पत्ति में प्राप्त आय पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार में लाभ

(1) किसी संबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में ही कर लगाया जाया जा तक कि वह उद्यम अथ संबिदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। यदि उद्यम पूर्णतः तरीके से कारोबार कर रहा हो

तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य से कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उतने अंश पर ही कर लगाया जा सकेगा जो कि उस स्थायी स्थापन के कारण हुआ हो।

(2) इस अनुच्छेद के परा 3 के उपबन्धों के अधीन जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य उस स्थायी स्थापन के कारण उसको उन लाभों का होंता माना जाएगा जिनके प्राप्ति होने की तब अपेक्षा रहती जब वह उन्हीं या वैसी परिस्थितियों में उन्हीं या धेरे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और निश्चित उद्यम होता और जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता हो। जहाँ स्थायी स्थापन के कारण होत वाले लाभों की रकम तत्काल निर्धारित नहीं की जा सकती हो अथवा उसके निर्धारण से विशेष कठिनाइयाँ पैदा होती हों तो स्थायी स्थापन के कारण होने वाले लाभों की उपयुक्त आधार पर आँका जाय।

(3) स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में व्ययों की उन कटौतियों की स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किये गये हों और उनमें इस प्रकार किये गये कार्यपातीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे चाहे वे उस राज्य में किये गये हों जहाँ स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र।

(4) कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन का हूण नहीं माने जायेगा कि उस स्थायी स्थापन द्वारा उद्यम के लिये मान अथवा पण्य बस्तुएँ खरीदी गयी हैं।

(5) पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों का तब तक, उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जायगा जब तक उनके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

(6) जहाँ लाभों में आय की वे मदें शामिल हों जिनका इस अधिनियम के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

जहाजरानी तथा विमान परिवहन

1. अन्तर्राष्ट्रीय जहाज अथवा विमान परिवहन के संचालन में प्राप्त लाभों पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जायगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित है।

2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम के प्रभावी प्रबन्ध का स्थान किसी पोत पर है, तो वह उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जायगा जिसमें पोत का अपना बन्दरगाह स्थित है अथवा यदि वहाँ इस प्रकार का कोई अपना बन्दरगाह नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जायगा, पोत का संचालक जिस राज्य का निवासी है।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किसी भूमि सेवा में किसी संयुक्त व्यापार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय यातायात एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों अथवा वायुयानों के संचालन से सम्बन्धित विधियों पर व्याज की ऐसे पोत अथवा वायुयान के संचालन से होने वाली आय के रूप में माना जायगा और अनुच्छेद II के उपबन्ध इस प्रकार के व्याज के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

5. 'पोतों' अथवा वायुयान संचालन' पदों का अर्थ होगा पोतों अथवा वायुयानों के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा अवैतकों (चार्टर्डर) द्वारा किया जाने वाला व्यक्तियों, डाक, पशुधन, अथवा माल के लाने से जाने का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की तरफ से ऐसे परिवहन के लिये

टिकटों की बिक्री, पोतों अथवा वायुयान का आनुपायिक पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित अन्य कोई कार्य शामिल है।

अनुच्छेद 9

अनुषंगी उद्यम

जहाँ:

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पूँजी में भाग लेते हैं, और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उपक्रमों के बीच वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हैं जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, यहाँ ऐसे कोई लाभ, उन शर्तों के होने का हलल में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त होते हुए होते हैं। किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किये जा सकेंगे। तथा तदनुसार उन पर कर लगाया जायगा।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. जो कम्पनी, एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भ्रदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे जिसकी लाभांश भ्रदा करने वाली कंपनी निवासी है तथा यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जायगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाये जाने वाले कर की रकम:

(क) लाभांशों की सकल रकम का 5 प्रतिशत से, यदि हितभागी स्वामी एक ऐसी कंपनी है जिसने लाभांशों की भ्रदायगी करने वाली कंपनी में प्रत्यक्षतः कम से कम 10 प्रतिशत पूँजी लगायी हुई है;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

यह पैराग्राफ, ऐसे लोगों के सम्बन्ध में, जिनमें से लाभांश का भुगतान किया जाता है, कंपनी के कराधान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होने हुए भी, भारत के किसी निवासी को किसी कंपनी द्वारा जो मारीशस की निवासी है, भ्रदा किये गये किसी लाभांश पर तब तक मारीशस में तथा मारीशस के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जब तक कंपनियों द्वारा, जो मारीशस की निवासी है, भ्रदा किये गये लाभांश के संबंध में उनके कराधेय लाभों की गणना के लिए, कटौती योग्य व्ययों के रूप में अनुमति दी जाती है। किन्तु बसूल किया गया कर, लाभांशों का भ्रदा करने वाली कंपनी के लाभों पर मारीशस कर की दर से अधिक नहीं होगा।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'लाभांशों' शब्द का अर्थ प्रायः, शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से, जो ऋण दावे नहीं हैं और लाभांशों में सट्टायगी हैं, प्राप्त आय से तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त ऐसी आय से है जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानून द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लगाये जाने की तरह से ही कर लगाया जाता है जिसकी वितरण करने वाली कंपनी एक निवासी है।

5. पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभार्थी का हिस्साभागी, जो किसी सविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे सविदाकारी राज्य में, जिसमें लाभार्थी अदा करने वाली कंपनी निवासी है, व्यापार करता है, वही स्थिति एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से, व्यापार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं संपन्न करता है और जिस धारिता के बारे में लाभार्थी की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप में सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, जैसी भी स्थिति हो अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबन्ध लागू होंगे।

6. जहां ऐसी कोई कंपनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किये गये लाभार्थ पर, किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के निवासी को ऐसे लाभार्थों को छोड़कर जो दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए गये हैं अथवा जहां तक कि जिस धारिता के सम्बन्ध में लाभार्थों की अदायगी की जाती है वहां उस राज्य में स्थित एक स्थायी स्थापन अथवा एक निश्चित आधार से प्रभावी रूप में सम्बन्ध है, उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जायगा और न ही कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभों संबंधी कर लगाया जायगा चाहे अदा किए गए लाभार्थ अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होंते हों तो लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक सविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जायगा।

2. तथापि, इस अनुच्छेद के पैरा 3 और 4 के उपबन्धों में दी गयी शर्तों के अनुसार, इस प्रकार के ब्याज पर भी, उस सविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जायगा जिसमें यह उत्पन्न होता है।

3. एक सविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज का उस राज्य में कर से छूट दी जायगी, बशर्त कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और उसका हिस्साभागी स्वामी हो;

- (क) अन्य सविदाकारी राज्य की सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण,
- (ख) अन्य सविदाकारी राज्य द्वारा स्थापित या संगठित की गयी कोई एजेंसी अथवा संस्था; अथवा
- (ग) ऐसा कोई बैंक, जो वास्तविक तौर पर बैंकिंग कारोबार चलाता है तथा जो अन्य सविदाकारी राज्य का निवासी है।

4. एक सविदाकारी राज्य में होने वाले ब्याज को, उस सविदाकारी राज्य में उस राज्य की सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा तक कर में छूट दी जायगी यदि यह ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा (पैरा 3 में उल्लिखित व्यक्ति को छोड़कर) प्राप्त किया गया हो या उसका उस पर हिस्साभागी स्वामित्व हो, जो दूसरे सविदाकारी राज्य का निवासी है, बशर्त कि इस संबंध में किये गये लेन-देन में उत्पन्न होने वाला ऋण संबंधी दावा प्रथमो-लिखित सविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

5. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'ब्याज' शब्द के अभिप्रेत प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी बांधों में प्राप्त आय है चाहे वे बंधक-पत्र द्वारा प्रतिभूत की गयी हो अथवा नहीं और चाहे उनको ऋणदाता के नामों में भारी-दागी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय तथा बंधक-पत्र अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधक-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों के संबंध में प्रदान

किये जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, देश में किए गए भुगतान पर लगाये गये अर्थवर्धन को ब्याज के रूप में नहीं माना जायगा।

6. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 4 के उपबन्ध इस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज पाने वाला किसी सविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण उस दूसरे सविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित निश्चित स्थान से स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो और जिस ऋण दावे के विषय में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी स्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबन्ध, लागू होंगे।

7. किसी सविदाकारी राज्य में ब्याज तभी उद्भूत हुआ माना जायगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं सविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उपसंजल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह सविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, सविदाकारी राज्य में उसका स्थायी प्रतिष्ठान है अथवा निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था और जिस पर ब्याज की अदायगी की गयी हो और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान द्वारा वसूल किया जाता है तब वह ब्याज सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जायगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

8. जहां ब्याज, अदा करने वाले तथा पाने वाले के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करते वाले और हिस्साभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती हो वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अवितरित भाग पर, इस कारण के अन्य उपबन्धों का अनुपालन करने हुए प्रत्येक सविदाकारी राज्य के अनुसार कर लगाया जायगा।

1. जो रायल्टियां एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत हों, और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की जाय वा वे उस दूसरे राज्य में कराधेय हो सकेंगी।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों पर उस सविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हैं, और उसी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा परन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द में सांश्रित्यक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति (जिनमें रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए स्वयंस्वर किन्हीं अथवा टेप शामिल हैं), कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिकार के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संचालित जानकारी के लिये प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस हालत में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टी को पाने वाला एक सविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे सविदाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थिति स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाया है, अथवा उस राज्य में स्थित निश्चित आधार से स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा संपत्ति के बारे

में रायल्टियों की प्रदायगी की जाती है ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित आधार में कारगर रूप में संबंधित है। ऐसे किसी मामले में, जैसी भी स्थिति हो, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उद्भूत हुईं तभी मानी जायेगी, यदि रायल्टी अदा करने वाला राज्य स्वयं कोई राजनैतिक उपमंडल स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहाँ रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में रायल्टी अदा करने की जिम्मेदारी है और इस प्रकार की रायल्टियों का वहन उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है सब ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत मानी जायगी जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहाँ रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गयी रायल्टियों की रकम, उसके तत्पश्चात्, अधिकार अथवा सूचना का ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए वे रायल्टियां अदा की जाती हैं उस रकम से बहुत जाती हैं जिसके लिए इस प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच सहमति हो गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में अदायगियों के अधिभाग पर इस प्रकार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जायगा।

अनुच्छेद 13

पूँजीगत लाभ

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अचल संपत्ति के अन्तरण से हुए लाभों पर, संविदाकारी राज्य में जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, कर लगाया जा सकेगा।

2. चल सम्पत्ति के अन्तरण से हुए लाभों पर जो किसी संविदाकारी राज्य के उपक्रम की स्थायी प्रतिष्ठान की उस व्यापारिक संपत्ति के अंग के रूप में अन्य संविदाकारी राज्य में स्थित है, अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को अन्य संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अर्थात् अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित आधार के अन्तरण से होने वाले लाभ भी शामिल है जिन पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलपोतों और वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलपोतों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

4. संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त लाभ पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जायेगा।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "अन्तरण" शब्द का अर्थ संपत्ति का बिक्रय, विनिमय, अन्तरण अथवा त्याग अथवा उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति अथवा अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रभूत किसी भी कानून के अंतर्गत उसका प्रनिर्वाह अधिग्रहण है।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार की अन्य स्वतंत्र सेवाओं के सम्बन्ध में अर्जित प्राय पर

केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक उस के पास अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में निश्चित आधार नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है। यदि उनके पास ऐसा निश्चित आधार है तो प्राय के केवल उतने भाग पर अन्य संविदाकारी राज्य में कर लगाया जायेगा जितना उस निश्चित आधार के कारण से हुआ है।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" शब्दों में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक साहित्यिक कलात्मक शैक्षणिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन मजदूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो उससे प्राप्त ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयुक्त नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही लगेगा यदि :—

(क) प्राप्तकर्ता, सगत "पिछले वर्ष" अथवा "प्राय वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिये दूसरे राज्य में मौजूद रहा है ; और

(ख) पारिश्रमिक की प्रदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गयी हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं किया गया हो जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उस उद्यम की प्रभावी प्रबंध व्यवस्था है।

अनुच्छेद 16

निर्देशक-शुल्क

संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निर्देशक मंडल के एक सदस्य की हैमियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निर्देशक फीस तथा उसी प्रकार की प्रदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकारों और जैसे सिनेटर, कलाकार, खेलाडी तथा अन्य कलाकार तथा संगीतकार और खिलाड़ियों को अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त प्राय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किये गये हों।

2. जहाँ मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा उसकी वैयक्तिक क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त प्राप्त स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो वहाँ उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस राज्य में कर लग सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे क्रियाकलाप किये जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी, जो संविदाकारी राज्य का निवासी है, द्वारा अन्य संविदाकारी राज्य में इस प्रकार किए गए उसके वैयक्तिक क्रियाकलापों से प्राप्त आय पर केवल प्रयोजनलिखित संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, यदि उन क्रियाकलापों को दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोजनलिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिसमें राजनैतिक सब-डिवीजन अथवा स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, पूर्णतः अथवा अंशतः सहायता दी गई हो।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी जहाँ मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा अपनी हैमियन में अन्य संविदाकारी राज्य में किए गए अपने वैयक्तिक क्रियाकलापों से प्राप्त आय जो मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त न हो कर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, उस आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा यदि उस अन्य व्यक्ति को दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिसमें राजनैतिक सब-डिवीजन अथवा स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, पूर्णतः अथवा अंशतः सहायता दी गई हो।

अनुच्छेद 18

सरकारी कार्य

1. किसी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को, जो उस राज्य का राष्ट्रिक है, उस राज्य में की गई सेवाओं के संबंध में प्रदत्त पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को, जो उस राज्य का राष्ट्रिक है, प्रदत्त पेंशन पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य सरकार द्वारा लाभार्थ चलाये गये कारोबार के संबंध में की गयी सेवाओं के लिए प्रदत्त पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू नहीं होगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध दूसरे संविदाकारी राज्य को, उस दूसरे राज्य की सहमति से अनुमोदित किसी विशेषज्ञ अथवा शाल-निर्देशक को किसी संविदाकारी राज्य के विकास सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उस राज्य द्वारा की गयी निधि में से प्रदत्त पारिश्रमिक पर इसी प्रकार से लागू होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "सरकार" शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों की कोई भी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण, विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक तथा मारीशन का बैंक शामिल होंगे।

अनुच्छेद 19

नगर सरकारी पेंशन तथा वार्षिकियां

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त की जा रही पेंशन अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न, और वार्षिकी पर कर केवल प्रयोजनलिखित संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा।

2. "पेंशन" शब्द का अर्थ उस नियतकालिक भुगतान से है जो विगत समय में की गयी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोट की अनिवार्यता के रूप में प्राप्त किया गया हो।

3. "वार्षिकी" शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिए पदावगिया करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन पर्वन्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अनुच्छेद 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को जा एत संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले संविदाकारी राज्यों में से एक का निवासी है अथवा था, और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रयोजनलिखित राज्य में उपस्थित है, दूसरे संविदाकारी राज्य में:—

(क) उस संविदाकारी राज्य से बाहर के स्रोतों से भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गयी अवाधगियों पर; तथा

(ख) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में "गत वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक पर, जो भारतीय मुद्रा में 15,000 रु० अथवा विनिमय की समान दर से उसी के बराबर मारीशन वर्षों से अधिक न हो वशत कि ऐसा रोजगार उसके अध्ययन से सीधे संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के लिए शुरू किया गया हो कर से छूट होगी।

2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जो शिक्षा अथवा लिए गए प्रशिक्षण के पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हानत में, किसी व्यक्ति को उस दूसरे संविदाकारी राज्य में पहुँचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए इस अनुच्छेद का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 21

प्राध्यापक, अध्यापक तथा शोध छात्र

1. एक प्राध्यापक, अध्यापक अथवा शोध छात्र को, जो संविदाकारी राज्यों में से एक संविदाकारी राज्य का, उस किसी विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन अथवा शोधकार्य के प्रयोजनार्थ अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ इस दूसरे संविदाकारी राज्य; अथवा किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अथवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्था के निमंत्रण पर, उस राज्य का दौरा करने के तुरन्त पूर्व निवासी है अथवा था, ऐसे प्रशिक्षण अथवा शोध के लिये उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहुँचने की तारीख से दो वर्ष की अनधिक अवधि के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद उस शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि यह शोधकार्य मूलतः विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह उस "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, निवासी है जिसमें "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" के तुरन्त पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का वह दौरा करता है।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "मान्यताप्राप्त संस्था" का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के मन्त्र प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गयी हो।

अनुच्छेद 22

अर्थ आय

1. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्वधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मर्दों पर, जहाँ कहीं उद्भूत हो, जिन्हें इस कगार के पिछले अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित अथवा संपत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उसमें स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं का उस दूसरे राज्य में निष्पादन करता है तथा अधिकार अथवा संपत्ति, जिसके संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी ढंग से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

अध्याय IV

बीहरे करारों के अपाकरण की पद्धतियाँ

अनुच्छेद 23

बीहरे करारों का अपाकरण

1. दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य में लागू कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के करारों के नियमन के लिए जारी रहेंगे, सिवाय इसके कि जहाँ इस अभिसमय में निहित उपबंधों के विपरीत उपबंध बनाये जाने हैं ।

2. (क) भारत के निवासी द्वारा मारीशस में उद्भूत लाभों की अथवा आय जिस पर भारत में तथा मारीशस, दोनों में कर देना पड़ता है, के संबंध में मारीशस के कानून के अधीन तथा इस कगार के उपबंधों के अनुसार नकद अथवा कटौती कर कर देय मारीशस कर की राशि को ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में संदेय भारतीय कर के प्रति जमा बार्की के रूप में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी जमा दिखायी जाने वाली ऐसी रकम (इस प्रकार की कोई जमा स्वीकार करने से पूर्व संगणित) उस भारतीय कर से अधिक नहीं होगी जो मारीशस में उद्भूत लाभों अथवा आय के अनुरूप हो । इसके अलावा, जहाँ निवासी एक कोई कंपनी है जिसे भारत में अतिरिक्त जमा करना है, वहाँ उपर्युक्त जमा प्रथमतः कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर के संदर्भ में मानी जाएगी और यदि कोई रकम शेष रहती हो तो वह उसके द्वारा भारत में देय अतिरिक्त के संदर्भ में, जमा मानी जाएगी ।

(ख) मारीशस की निवासी किसी कंपनी द्वारा भारत की निवासी किसी कंपनी को, जो लाभों अदा करने वाली कंपनी में कम से कम 10% शेयर धारण करती है, प्रदत्त ऐसे किसी लाभों के मामले में, ऐसे लाभों के संबंध में, जिसमें से ऐसा लाभों दिया जाता है, कंपनी द्वारा देय मारीशस कर को जमा के रूप में स्वीकार की जाने वाली रकम को हिसाब में लिया जाएगा, (यह ऐसे किसी मारीशस कर के अलावा होगी जिसे इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के उपबंधों के अंतर्गत जमा के रूप में स्वीकार किया जा सके) ।

3. पैराग्राफ 2 में उल्लिखित जमा के रूप में स्वीकार की जाने वाली रकम के प्रयोजनार्थ 'संदेय मारीशस कर' शब्दों में निम्नलिखित के अंतर्गत उस वर्ष के संबंध में अथवा उसके किसी भाग के लिए स्वीकृत

कर में छूट अथवा कटौती को छोड़कर, ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जाएगी जो किसी वर्ष के लिये मारीशस के कर के रूप में देय रही हो:-

(i) मारीशस आयकर अधिनियम (1974 का 41) की धारा 33, 34, 34क और 34ख;

(ii) कोई अन्य उपबंध जो छूट अथवा कटौती प्रदान करने के लिए बाद में बनाये जाएँ और आर्थिक विकास के प्रयोजनार्थ जिनके लिए संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी सहमत हों ।

4. (क) मारीशस के किसी निवासी द्वारा भारत में उत्पन्न ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में जिस पर भारत तथा मारीशस दोनों ही देशों में कर लगा हो भारतीय कानूनों के अंतर्गत तथा इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार चाहे प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा, संदेय भारतीय कर की रकम, ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में संदेय मारीशस कर के प्रति जमा के रूप में अनुज्ञान की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की जमा, मारीशस के कर से (इस प्रकार की जमा अनुज्ञान करने से पूर्व यथा संगणित रूप में), जो भारत में उद्भूत लाभों अथवा आय के उपयुक्त हो, अधिक न हो ।

(ख) किसी कंपनी द्वारा, जो भारत का निवासी हो, किसी ऐसी कंपनी को जो मारीशस की निवासी हो और जो लाभों अदा करने वाली कंपनी के कम से कम 10% शेयरों को मालिक हो, द्वारा प्रदत्त लाभों के संबंध में, उक्त जमा में (किसी ऐसे भारतीय कर के अलावा जिसके लिए इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के उपबंधों के अंतर्गत जमा की स्वीकृति दी जा सकती हो) जमा की जाने वाली रकम में ऐसे लोगों के बारे में, जिसमें से ऐसे लाभों की अदायगी की गई हो, कंपनी द्वारा देय भारतीय कर को हिसाब में लिया जाएगा ।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित जमा के प्रयोजनार्थ 'देय भारतीय कर' पद में ऐसी रकम को शामिल समझा जाएगा जिसके बराबर,—

(i) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (4), 10(4क), 10(6), (VIIक), 10(15) (IV) 10(28), 10क, 32क, 33क, 35ख, 54ख, 80ज, 80जक, 80झ तथा 80ड के अंतर्गत विविध प्रेरक उपायों द्वारा कर में कमी कर दी गयी है, तथा

(ii) कोई अन्य उपबंध जो बाद में ऐसे कर की कटौती देने के लिए अधिनियमित किया जाए, जिनके बारे में संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी आर्थिक विकास के प्रयोजनार्थ सहमत हों ।

6. जहाँ इस अभिसमय के अंतर्गत एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय के संबंध में उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, तब प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करने में कर की वही दर लागू कर सकता है जो इस अभिसमय के अनुसार कर से छूट की गई आय को छूट न दिए जाने की स्थिति में लागू होती ।

अध्याय V

विशेष उपबंध

अनुच्छेद 24

समस्यवहार

(1) एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रको पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई करारों व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस करारों से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है ।

(2) किसी संविदाकारी राज्य के उद्देश्य के, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा करारों लागू नहीं किया

कराधान को उपाय होने या नहीं हो, उन्हें परिस्थितियों में अथवा धीमा ही स्थितियों के अंतर्गत प्रारम्भ उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुसूत हों।

(3) इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उससे एक संविदाकारी राज्य को, उस राज्य के अधिात, व्यष्टियों को, करगणन के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व वैयक्तिक छूटें, राहतें, छटीयों तथा कटीयों प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को ही उपलब्ध है।

(4) एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक अनिवासीयों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसा अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर वैसे ही परिस्थितियों में लागू होती है, अथवा हो सकती हैं।

(5) इस अनुच्छेद में 'कराधान' पद का अर्थ वे कर हैं जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यबंधि

(1) जहां किसी संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझना है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के हानि हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निश्चिंत है। यह मामला, उस कार्य के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके कारण इस अभिसमय के प्रतिकूल कराधान हुआ है।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हों तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। जो भी करार हो गया हो, वह संविदाकारी राज्य के कानूनों में निहित किसी समय सीमा के हानि के बावजूद भी कार्यान्वित किया जाएगा।

(3) इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाई अथवा शंका उत्पन्न हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में दाह कराधान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर सकेंगे जिनकी व्यवस्था अभिसमय में नहीं की गई है।

(4) पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय के अंतर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जहां कोई करार करने हेतु शिखरों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो वहां ऐसा आदान-प्रदान एक अंतरांग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद—26

सूचना अथवा वस्तावेज का आदान-प्रदान

1 संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी इस अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा कर अपवर्धन को रोकने के लिए जो

इस अभिसमय का विषय है, इस प्रकार की सूचना अथवा दस्तावेजों का तो आवश्यक हो, आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जाएगा परन्तु इन्हें ऐसे व्यक्तियों (जिनमें न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी सम्मिलित हैं) के समक्ष प्रकट किया जा सकता है जो इस अभिसमय के विधानान्तर्गत करों के निर्धारण, वसूली, प्रवर्धन, जांच अथवा अभियोजन में गम्भीर हैं अथवा यह ऐसे व्यक्तियों को प्रकट की जा सकती है जिससे इस सूचना अथवा दस्तावेज का सम्बन्ध हो।

2 सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी तौर पर अथवा किसी मामले विशेष के संदर्भ में अनुरोध के आधार पर अथवा दांतों तरह से किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर, नेमी आधार पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे।

3 पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य किया जाय :—

(क) संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रणामनिक परिगाटी से हट कर कोई प्रणामनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जो उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा सामान्य प्रणामनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो सकते।

(ग) कोई ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिसमें कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक भेद प्रकट हो जाएगा अथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया या सूचना सप्लाई करना जिसका प्रकटन सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा।

अनुच्छेद—27

राजनयिक तथा कौसली कार्य

इस अभिसमय में निहित किसी व्यवस्था का, अंतर्राष्ट्रीय विश्वि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौसली अधिकारियों के राज्य कर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय VI

अन्तिम व्यवस्था

अनुच्छेद 28

प्रवर्धन

हर संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को, इस अभिसमय को प्रवर्धित करने के लिए अपने कानून द्वारा अपेक्षित कार्यविधियों के पुरा हो जाने के बारे में अधिमूचित करेगा। यह अभिसमय, इन अधिमूचनाओं में से बाद वाली अधिमूचना की तारीख को लागू होगा और उसके बाद;

(क) भारत में, 1 अप्रैल, 1983 को अथवा इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर-निर्धारण योग्य आय तथा पुंजीगत लाभों के संबंध में;

(ख) मारीशल में, 1 जुलाई, 1983 को अथवा उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष में कर-निर्धारण योग्य आय तथा पुंजीगत लाभों के संबंध में लागू होगा।

अ.स.सं.सं. २०१

अ.स.सं.सं.

यह अभिसमय सन्धिपत्र तथा एक समुदाय परन्त दोनो मे से कोई भी संविदाकारी राज्य का अभिसमय के साथ हानि के पालन को प्रवृत्ति पनी हो जाने पश्चात् भारत में जाने वाले निम्नी भी कैलेण्डर वर्ष के 30 जून की अवस्था उपरि उक्त, साधारण साधारण, उक्त संविदाकारी राज्य को. सन्धि सन्धि तथा निम्नी नोटिस दे सकता है और ऐसी स्थिति में यह अभिसमय

- (क) भारत में, जिस वर्ष नोटिस दिया जाए उक्त कैलेण्डर वर्ष के बाद जाने वाले दुधरे कैलेण्डर वर्ष में 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष और पश्चात् हर निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारणीय आय और पूंजीगत लाभों के संबंध में;
- (ख) मारीशस में, जिस वर्ष नोटिस दिया जाए उक्त कैलेण्डर वर्ष के बाद जाने वाले दुधरे कैलेण्डर वर्ष में कर-निर्धारण वर्ष में, 1 जुलाई से आरम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष और पश्चात् हर निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारणीय आय और पूंजीगत लाभों के संबंध में समाप्त हो जाएगा।

जिनके साथ में इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

पोर्ट लुई में अगस्त, 1982 के चौबीसवें दिन को द्वितीय ग्रेट ब्रिटेन भाषायों में से एक को दो भाग प्रतियों में दिया गया, इसके दोनो भाग साधारण प्रतियों होंगे। दोनो भागों में भिन्नता यदि की स्थिति में अग्रज भाग ही प्रभावी होगा।

हस्ता. ०

भारत सरकार की ओर से

हस्ता. ०/-

मारीशस सरकार को आगे से

[फा. सं. 501/20/73-7. फटीडी]

श्री: छापू निरुक्त, मन्त्रालय सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(FOREIGN TAX DIVISION)

New Delhi, the 6th December, 1983

NOTIFICATION

INCOME TAX

G.S.R. 920(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Mauritius for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains and for the encouragement of mutual trade and investment has come into force on the notification by both the Contracting States to each other of completion of the procedures required by their respective laws, as required by Article 28 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies

(Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention, shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION

BETWEEN

The Government of the Republic of India and
The Government of Mauritius for
The avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to Taxes of Income and Capital Gains

The Government of the Republic of India and
the Government of Mauritius

DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains and for the encouragement of mutual trade and investment

HAVE AGREED as follows :

CHAPTER 1

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The existing taxes to which this Convention shall apply are :

(a) in the case of India :

(i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964); (hereinafter referred to as "Indian tax").

(b) in the case of Mauritius :

the income tax (hereinafter referred to as "Mauritius tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any signifi-

cant changes which are made in their respective taxation laws.

CHAPTER II DEFINITIONS

Article 3

General Definition.

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term 'India' means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (Act, No. 80 of 1976), in which India has certain rights and to the extent that these rights can be exercised therein as if such maritime zone is a part of the territory of India;
- (b) the term 'Mauritius' means all the territories, including all the islands, which in accordance with the laws of Mauritius, constitute the State of Mauritius and includes
 - (i) the territorial sea of Mauritius; and
 - (ii) any area outside the territorial sea of Mauritius which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of Mauritius concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of Mauritius with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;
- (c) the terms 'a Contracting State' and 'the other Contracting State' mean India or Mauritius as the context requires;
- (d) the term 'tax' means Indian tax or Mauritius tax as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term 'person' includes an individual, a company and any other entity, corporate or non-corporate, which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term 'company' means any body corporate or any entity which is treated as

a company or a body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

- (g) The terms 'enterprise of a Contracting State' and 'enterprise of the other Contracting State' mean respectively an industrial, mining, commercial, plantation or agricultural enterprise or similar undertaking carried on by a resident of a Contracting State and an industrial, mining, commercial, plantation or agricultural enterprise or similar undertaking carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term 'competent authority' means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Mauritius, the Commissioner of Income Tax or his authorised representative;
- (i) the term 'national' means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any local person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
- (j) the term 'international traffic' means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated by the enterprise solely between places in the other Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires have the meaning which it has under the laws in force of that Contracting State relating to the areas which are the subject of this Convention.

Article 4

RESIDENTS

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of similar nature. The terms "resident of India" and "resident of Mauritius" shall be construed accordingly.

2. When, by reason of the provision of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the

purposes of this Convention shall be determined in accordance with the following rules:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interest cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term 'permanent establishment' means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term 'permanent establishment' shall include:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others;

- (g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on;
- (i) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than nine months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term 'permanent establishment' shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely—
 - (i) for the purpose of advertising,
 - (ii) for the supply of information,
 - (iii) for scientific research, or
 - (iv) for similar activities.

which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, a person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State (other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 5 apply) shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if:

- (i) he has and habitually exercises in that first mentioned State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (ii) he habitually maintains in that first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise

from which he regularly fulfils orders on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted exclusively or almost exclusively on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not, of itself, constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources, ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the

enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. Where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment cannot be readily determined or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is abroad a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated,

or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is resident.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. For the purposes of paragraph 1, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

5. The term "operation of ships or aircraft" shall mean business of transportation of persons, mail, livestock or goods, carried on by the owners or lessees or charterers of the ships or aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of ships or aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the

beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

- (a) five per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;
- (b) fifteen per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, dividends paid by a company which is a resident of Mauritius to a resident of India may be taxed in Mauritius and according to the laws of Mauritius, as long as dividends paid by companies which are residents of Mauritius are allowed as deductible expenses for determining their taxable profits. However, the tax charged shall not exceed the rate of the Mauritius tax on profits of the company paying the dividends.

4. The term 'dividends' as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State.

3. Interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (a) the Government or a local authority of the other Contracting State ;
- (b) any agency or entity created or organised by the Government of the other Contracting State ; or
- (c) any bank carrying on a bonafide banking business which is a resident of the other Contracting State.

4. Interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person (other than a person referred to in paragraph 3) who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

5. The term 'interest' as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and, in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

6. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting

State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12 ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State, where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, gains from the alienation of ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be taxable only in that State.

5. For the purposes of this Article, the term "alienation" means the sale, exchange, transfer,

or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition thereof under any law in force in the respective Contracting States.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term 'professional services' includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in first mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised on board a ship or aircraft in international traffic, may be taxed only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians, and by athletes, from their personal activities as much may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income is derived from personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such, and accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if those activities in the other Contracting State, are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article and Articles 7, 14 and 15, where income is derived from personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State and accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

Article 18

GOVERNMENTAL FUNCTIONS

1. Remuneration, other than pension, paid by the Government of a Contracting State to an individual who is a national of that State in respect

of services rendered to that State, shall be taxable only in that State.

2. Any pension paid by the Government of a Contracting State to an individual who is a national of that State, shall be taxable only in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purpose of profit.

4. The provisions of paragraph 1 of this Article shall likewise apply in respect of remuneration paid under a development assistance programme of a Contracting State, out of funds supplied by that State, to a specialist or volunteer seconded to the other Contracting State with the consent of that other State.

5. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local or statutory authority of either Contracting State and, in particular, the Reserve Bank of India and the Bank of Mauritius.

Article 19

Non-Government Pensions and Annuities

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 18, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State shall be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other Contracting State on :

(a) payments made to him from sources outside that other Contracting State

for the purposes of his maintenance, education or training; and

- (b) remuneration from employment in that other Contracting State, in an amount not exceeding Rs. 15,000 in Indian currency or its equivalent in Mauritius rupees at the parity rate of exchange during any "previous year" or "year of income" as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A Professor, Teacher and Research Scholar who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State or of a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at the university, college, school or other approved institution, shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other Contracting State.

2. This Article shall not apply to income from research if the research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 20 an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income" as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".

4. For the purpose of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. (a) The amount of Mauritius tax payable, under the laws of Mauritius and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of profits or income arising in Mauritius, which has been subjected to tax both in India and in Mauritius, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in Mauritius. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

(b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of Mauritius

to a company which is a resident of India and which owns at least 10 per cent of the shares of the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Mauritius Tax for which credit may be allowed under the provisions of subparagraph (a) of this paragraph) the Mauritius tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

3. For the purposes of the credit referred to in paragraph 2, the term 'Mauritius tax payable' shall be deemed to include any amount which would have been payable as Mauritius tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under :

- (i) section 33, 34, 34A and 34B of the Mauritius Income-tax Act (41 of 1974);
- (ii) any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development.)

4. (a) The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Mauritius, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and Mauritius shall be allowed as a credit against Mauritius tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Mauritius tax (as computed before allowing any such credit) is appropriate to the profits or income arising in India.

(b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Mauritius and which owns at least 10 per cent of the shares of the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Indian Tax for which credit may be allowed under the provisions of subparagraph (a) of this paragraph) the Indian tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.)

5. For the purposes of the credit referred to in paragraph 4, the term 'Indian tax payable' shall be deemed to include any amount by which

tax has been reduced by the special incentive measures under :

- (i) section 10(4), 10(4A), 10(6) (viiia), 10(15)(iv), 10(28), 10A, 32A, 33A, 35B, 54E, 80HIL, 80HHA, 80-I, 80L of the Indian Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
- (ii) any other provision which may subsequently be enacted granting a reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development.

6. Where under this Convention a resident of Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first mentioned Contracting State may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Convention had not been so exempted.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

Non-Discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourable levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

Exchange of Information or Document

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for prevention of evasion of taxes which are the subject of this Convention. Any information or document so exchanged shall be treated on secret but may be disclosed to persons (including courts or

other authorities) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Convention, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. The provisions of paragraph 1 shall not be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

Diplomatic and Consular Activities

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 28

Entry Into Force

Each of the Contracting State shall notify to the other completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

- (a) in India, in respect of income and capital gains assessable for any assessment year commencing on or after 1st April, 1983;

- (b) In Mauritius, in respect of income and capital gains assessable for any assessment year commencing on or after 1st July, 1983.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this convention shall cease to have effect:

- (a) in India, in respect of income and capital gains assessable for the assessment year commencing on 1st day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years;

- (b) in Mauritius, in respect of income and capital gains assessable for the assessment year commencing on 1st day of July in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present convention.

Done on this 24th day of August, 1982 at Port Louis on two original copies each in the Hindi and English languages, both the texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

Sd/-

Sd/-

For the Govt. of India. For the Govt. of Mauritius

[F. No. 501/20/73-FTD]

C. K. TIKKU, Jt. Secy.